



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 2 दिसम्बर, 2005/11 अग्रहायण, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग शिमला

अधिसूचना

शिमला-171 002, 30 नवम्बर, 2005

संख्या एच०पी०ई०आर०सी०/428.— हिमाचल प्रदेश राज्य में किसी व्यक्ति को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के विक्रय तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत उपापन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रारूप विनियम, जिन्हें हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 86 की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) तथा धारा 181 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सशक्त करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करता है, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 181 की उप-धारा (3) द्वारा यथोपेक्षित के अनुसार उनसे आम प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिये प्रकाशित किए जाते हैं और एतद्वारा यह नोटिस (सूचना) दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर, इनके राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में प्रकाशित होने की तारीख से तीस (30) दिन के अवसान पर, किसी भी आक्षेप या सुझाव सहित, जो इस बाबत उक्त अवधि के भीतर प्राप्त हुआ हो/हुए हों, विचार किया जाएगा।

इस निमित्त आक्षेप या सुझाव सचिव, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, क्योथल कमर्शियल काम्पलेक्स, खलिनी, शिमला को सम्बोधित किए जाने चाहिए ।

प्रारूप विनियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन) विनियम, 2005 है।

- (2) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।
- (3) ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं.— इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “अधिनियम” से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;
- (ख) “आयोग” से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;
- (ग) “क्रय मात्रा” से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से क्रीत विद्युत का इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिशत अंश अभिप्रेत है। उक्त मात्रा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित उत्पादन केन्द्रों से सभी प्रत्यक्ष क्रयों तथा अन्य अनुज्ञापिधारी से किए गये क्रय, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उद्भूत हो, का जोड़ होगी;
- (घ) “नवीकरणीय स्रोत” से इस संदर्भ में, गैर-पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन स्रोत, अभिप्रेत है जिनमें 25 मैगावाट की क्षमता तक की लघु जल विद्युत परियोजनाएं, पवन, सौर, जैव द्रव्यमान अनुपाती अभिक्रिया (जिसमें चीनी कारखाने का सह-उत्पादन भी आता है) शहरी/नगरीय कचरा स्रोत तथा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दूसरे अन्य स्रोत भी आते हैं;
- (ङ) “राज्य” से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है; तथा
- (च) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और यहाँ परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन के लिए अधिनियम में नियत किए गए हैं। उन पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं परन्तु विशेष रूप में इन विनियमों में अथवा अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु सक्षम विधानमण्डल द्वारा पारित और राज्य में विद्युत उद्योग में लागू किसी विधि में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उक्त विधि में नियत किये गए हैं। उन पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं परन्तु विशेष रूप से इन विनियमों में अथवा अधिनियम में अथवा सक्षम विधान मण्डल द्वारा पारित विधि में परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो सामान्यतः उनके लिए विद्युत उद्योग में दिए जाते हैं ।

3. नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत क्रय मात्रा.— (1) आबद्ध उपयोग तथा तीसरे पक्ष को विक्रय के बाद, उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्रीत की जाएगी।

(2) नवीकरणीय ऊर्जा का ग्रिड के माध्यम से जोड़ने, पारेषण अथवा चक्रण को अधिमान दिया जाएगा।

(3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपनी राजस्व गणना दाखिल करते समय आगामी वर्ष के लिए नवीकरणीय स्रोतों से अपनी क्रय मात्रा का, पर्याप्त प्रमाण सहित, उल्लेख करेगा।

(4) वितरण अनुज्ञप्तिधारी उन नवीकरणीय स्रोतों, जिन से वह नवीकरणीय ऊर्जा क्रय करने का विचार रखता है, का उल्लेख करेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी, जहां तक सम्भव हो, नवीकरणीय ऊर्जा अपने प्रदाय क्षेत्र में नवीकरणीय स्रोतों से ही प्राप्त करेगा।

(5) आयोग, प्रत्येक तीन वर्ष के अन्तराल में एक बार, या जब कभी आवश्यक हो उससे कम अन्तराल पर भी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए नवीकरणीय स्रोत से नियत क्रय मात्रा को पुनर्निरीक्षित कर सकेगा :

परन्तु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए नवीकरणीय स्रोतों से क्रय मात्रा का प्रथम पुनर्निरीक्षण इन विनियमों के प्रारम्भ के पाँच वर्ष की अवधि के अवसान पर ही होगा।

(6) आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर, प्रदाय की मजबूरियों तथा अन्य अनियन्त्रित कारणों के अध्यधीन रहते हुए, उप-विनियम (1) में अधिकथित क्रय मात्रा का अधित्यजन कर सकेगा।

4. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अभिवृद्धि.— कोई भी व्यक्ति, जो नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन करता है, स्थापित क्षमता का विचार किए बिना, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण प्रणाली और/या वितरण प्रणाली या ग्रिड तक हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (खुली पहुँच हेतु निबन्धन एवं शर्तों) विनियम, 2005 के अन्तर्गत आदेशात्मक खुली पहुँच का हकदार होगा। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य पारेषण उपयोगिता, उक्त व्यक्ति के आवेदन पर, समुचित अन्तरासंयोजन सुविधाएं उपलब्ध करेगा तथा उक्त अन्तरासंयोजन उन संयोजन शर्तों के, जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग से सक्रिय विचार-विमर्श करने के उपरान्त, अवधारित की जाएँ, तथा विद्युत को ग्रिड से जोड़ने के लिए प्राधिकरण द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुकूल होगा:

परन्तु यह कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक, इस में सुधार में केवल अन्तरासंयोजन बिन्दु तक ही उस द्वारा किए गये युक्तियुक्त व्यय का, यदि कोई हो, वहन करेगा।

5. **टैरिफ का अवधारण.**— आयोग नवीकरणीय स्रोत से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत क्रय के लिए टैरिफ आधार वर्ष 2001 पर 2 रुपये 50 पैसे प्रति युनिट होगा:

परन्तु यह कि टैरिफ उपभोक्ता मूल्य इन्डैक्स की वार्षिक मुद्रास्फीति का 50 प्रतिशत होगी। मुद्रास्फीति का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादक द्वारा अवशोषित किया जाएगा और मुद्रास्फीति का 50 को आधार दर में जोड़ा जाएगा:

परन्तु यह और कि जब तक कि कानूनी उपबन्धों या नियमों या राज्य सरकार की नीति में कोई बदलाव नहीं आता है, इन विनियमों की अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निष्पादित विद्युत क्रय के करारों के उपबन्ध, उस अवधि में, जिसका उक्त विद्युत क्रय के करारों में उल्लेख है, लागू रहेंगे और उसके उपरान्त इन विनियमों के उपबन्ध लागू होंगे।

6. **कठिनाईयाँ दूर करने की शक्ति.**— यदि इन विनियमों में किसी उपबन्ध को लागू करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है, तो आयोग, स्वतः अथवा आवेदन पर, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी समुचित कार्रवाई, जो अधिनियम के असंगत न हो और आयोग को कठिनाई दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक तथा समचीन हो, करने के लिए निर्देशित कर सकेगा।

7. **आदेशों तथा व्यवहार सम्बन्धी निर्देश जारी करना.**— अधिनियम तथा इन विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आयोग, समय-समय पर, इन विनियमों के कार्यान्वयन तथा उक्त कार्यान्वयन के बारे में प्रक्रिया अपनाने तथा उसके प्रासंगिक अथवा सहायक मामलों के सम्बन्ध में आदेश और व्यवहार सम्बन्धी निर्देश जारी कर सकता है।

8. **निर्वचन.**— इन विनियमों के निर्वचन से सम्बन्धित सभी विवादक आयोग द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे तथा उन पर आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा।

आयोग के आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित /—

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

**HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
SHIMLA**

NOTIFICATION

Shimla, the 30th November, 2005

No. HPERC/428.—The following draft regulations for promoting the sale of power from renewable sources to any person and power procurement from renewable sources by the distribution licensee within the State of Himachal Pradesh, which the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission proposes to make in exercise of the powers conferred under clause (e) of sub-section (1) of section 86 and sub-section (1) of section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, are hereby published, as required by sub-section (3) of section 181 of the said Act, for the information of all the persons likely to be affected thereby; and, notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections or suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto.

The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla – 171 002.

DRAFT REGULATIONS

1. Short title, extent and commencement .— (1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Power Procurement from Renewable Sources) Regulations, 2005.

(2) These regulations shall extend to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003);

- (b) “Commission” means the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission;
- (c) “quantum of purchase” means the percentage share of purchase of electricity, from renewable sources as specified in these regulations. The quantum would be the sum of all direct purchase from generation stations based on renewable sources and purchase from any other licensee, which would arise from renewable sources;
- (d) “renewable sources” in this context means non-conventional, renewable electricity generating sources such as small hydro power projects upto 25 MW capacity, wind, solar, biomass (including sugar mill co-generation), urban/municipal waste, or other such sources as approved by the Central or the State Government;
- (e) “State” means the State of Himachal Pradesh; and
- (f) the words and expressions used and not defined in these Regulations but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Acts. Expressions used herein but not specifically defined in these Regulations or in the Act but defined under any law passed by a competent legislature and applicable to the electricity industry in the State shall have the meaning assigned to them in such law. Expressions used herein but not specifically defined in the Regulations or in the Act or any law passed by a competent legislature shall have the meaning as is generally assigned in the electricity industry.

3. Quantum of purchase of electricity from renewable sources.—(1) Renewable energy available after the captive use and third party sale shall be purchased by the distribution licensee(s).

(2) The priority should be given for connectivity/transmission/wheeling of renewable energy through grid system.

(3) The distribution licensee shall indicate, alongwith the sufficient proof thereof, the quantum of purchase from renewable sources for the ensuing year inthe ARR filing.

(4) The distribution licensee shall indicate the renewable sources from which it plans to purchase the renewable energy. The distribution licensee to the extent possible shall source the renewable energy from renewable sources within his area of supply.

(5) The Commission may review the quantum of purchase from renewable sources by a distribution licensee once in every 3 years or at lesser intervals as may be necessary:

Provided that the first review of the quantum of purchase from renewable sources by the distribution licensee, shall be done after the expiry of five years from the commencement of these regulations.

(6) Subject to supply constraints or any other uncontrollable factors, the Commission may, at the request of the distribution licensee, waive off the quantum of purchase laid down under sub-regulation(1).

4. Promotion of renewable sources of energy.—Any person generating electricity from renewable sources, irrespective of installed capacity shall have mandatory open access to any licensee's transmission system and/or distribution system or grid, as the case may be under the HPERC (Terms and Conditions or Open Access) Regulations, 2005. On an application from such person, the transmission licensee or distribution licensee or the State Transmission Utility shall provide appropriate inter-connection facilities, and such inter-connection shall be consistent with the connectivity conditions as may be determined by the Licensee in active consultation with the Commission and also the grid connectivity standards as may be specified by the Authority:

Provided that the person generating renewable energy shall bear the expenditure reasonably incurred for the up-gradation, if any, upto inter-connection point only.

5. Determination of tariff.—The tariff for the purchase of electricity from renewable sources by the distribution licensee shall be Rs. 2.50 per unit with the base year 2001:

Provided that the tariff shall be indexed at 50% of the annual inflation rate of the consumer Price Index. The inflation upto 50% shall be absorbed by the generator of the renewal energy and 50% inflation shall be added to the base rate:

Provided further that unless there is change in the statutory laws, or rules or the State Government Policy, the Power Purchase Agreements entered into by a licensee, prior to the notification of these regulations shall continue to apply for such period as mentioned those Power Purchase Agreements and thereafter provisions of these regulations shall apply.

6. Power to remove difficulties.—In case of any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these regulations, the Commission may, either *suo motu* or on an application made to it, do or undertake to do things, or by general or special order direct the licensee to take suitable action, not being inconsistent with the Act, which appears to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

7. Issue of orders and directions.—Subject to the provisions of the Act and these regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions with regard to the implementation of these regulations and procedure to be followed for such implementation and matter incidental or ancillary thereto.

8. Interpretation.— All issues arising in relating to interpretation of these regulations shall be determined by the Commission and the decision of the Commission on such issues shall be final.

By the order of the Commission,

Sd/—

Secretary

Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission.